

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 321
No. 22]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938	[N.C.T.D. No. 321

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

क्रम सं. : एफ/29/17/ईपीएफ(एकजेम्प-4686)/लैब/16/4110.—जबकि मै0 आर.एच.सी. होल्डिंग्स प्रा. लि., नई दिल्ली (डीएल/4686) ( इसके आगे स्थापना/प्रतिष्ठान के रूप में कहा जायेगा ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 के खंड 1 ( इसके आगे अधिनियम के रूप में कहा जायेगा ), के तहत छूट के लिये आवेदन किया है।

जबकि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की उप समिति द्वारा दिनांक 07.08.2014 को अपनी बैठक में उक्त स्थापना को खंड 17 (1) के तहत छूट दिये जाने की सिफारिश दिनांक 19.9.2006 से की है।

जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल की राय में किसी भी स्थापना के द्वारा भविष्य निधि में योगदान भविष्य निधि के नियम धारा 6 में निर्दिष्ट की तुलना में कम नहीं होगा और कर्मचारी को उसी तरह की किसी अन्य स्थापना में भी भविष्यनिधि के सभी लाभ भी पाता रहेगा जो की उपरोक्त धारा अथवा भविष्यनिधि योजना, 1952 में दिये गये हैं (इसके आगे कथित योजना के रूप में कहा जायेगा )

अब इसलिये धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अधिनियम, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना संख्या पी.एफ.-11.11 (40)/59 दिनांक 22.4.1960 उपराज्यपाल, दिल्ली एतद्वारा अनुलग्न अनुसूचित शर्तों के तहत उक्त स्थापना को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत दिनांक 15.9.2009 से छूट प्रदान करते हैं

अनुसूचि

- नियोक्ता द्वारा अपनी अध्यक्षता में भारत सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भविष्यनिधि के प्रबंधन के लिये समय समय पर न्यासी मंडल का गठन किया जायेगा। भविष्य निधि न्यासी मंडल के निहित में होगा जो पूर्ण रूप से उचित खातों व भविष्य निधि में लेखा में प्राप्ति व भुगतान के लिये जवाबदेह होगा तथा प्रयोजन के लिये नियोक्ता का निर्णय प्रतिष्ठानों के मामले में अंतिम होगा।

2. न्यासी मंडल हर तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा और समय समय पर केन्द्र सरकार / केन्द्र भविष्यनिधि आयुक्त, सी.पी.एफ.सी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
3. सभी नियोक्ता, अधिनियम की धारा 2 के तहत, जिसे भविष्य निधि का सदस्य बनने के लिये पात्रता किया गया है, स्थापना छूट नहीं दी गयी है, के सदस्यों के रूप में नामांकित किया जायेगा।
4. जहां एक कर्मचारी जो पहले से ही कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य है, या भविष्य निधि की किसी अन्य छूट का सदस्य है, और प्रतिष्ठान में कार्यरत है, नियोक्ता द्वारा उस कर्मचारी को तुरंत ही फंड में सदस्य के रूप में दाखिल किया जायेगा। नियोक्त द्वारा भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता की ही तरह राशि स्थानांतरित करनी होगी।
5. नियोक्ता द्वारा तथा उसके कर्मचारी द्वारा महीने की हर 15 तारीख को, पिछले महीने का भविष्यनिधि राशि, समय समय पर अधिनियम के तहत निर्धारित दर पर न्यासी मंडल को स्थानांतरित करना देय होगा। नियोक्ता द्वारा न्यासी मंडल को उक्त बकाया भुगतान को स्थानांतरित करने में हुई किसी भी प्रकार की देरी के लिये अधिनियम की धारा 7 क्यू के प्रावधानों के संदर्भ में ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
6. नियोक्ता भविष्य निधि के प्रशासन सभी खर्च को वहन करेगा तथा भविष्य निधि के किसी अन्य नुकसान जैसे चोरी, डकैती, गबन तथा अन्य किसी कारण से नुकसान को पूरा करेगा।
7. न्यासी मंडल द्वारा घोषित ब्याज में किसी तरह की कमी को वैधानिक सीमा तक लाने की जिम्मेवारी नियोक्ता की होगी।
8. नियोक्ता द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूर, संशोधित नियमों तथा निधियों को, कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में स्थापना के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
9. योगदान के दर देय की स्थिति, अग्रिमों की मात्रा और स्थापना, प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा होने वाली ब्याज की राशि स्थापना तथा भविष्यनिधि के नियमों के अंतर्गत, सदस्य के मासिक चल संतुलन की गणना पर आधारित और न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित अधिनियम और योजना के तहत बनाये गये प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की तुलना में कम नहीं होनी चाहिये।
10. योजना में किसी प्रकार का संशोधन, जो कि कर्मचारी के लिये स्थापना के पहले नियमों से ज्यादा फायदेमंद होगा उसे मंडल के नियमों के अनुसार स्वचालित रूप से लागू किया जायेगा।
11. नियोक्ता द्वारा किसी भी नियम में कोई भी संशोधन भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। भविष्य निधि आयुक्त मंजूरी से पहले कर्मचारी को उसके नजरिये को समझाने को एक उचित अवसर देना होगा।
12. निकासी, अग्रिम व स्थानांतरण आदि के सभी मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार तेजी से निपटाये जायें।
13. न्यासी मंडल प्रत्येक कर्मचारी के सम्बंध में उसके द्वारा किया गया योगदान, निकासी व ब्याज के लिये विस्तृत खाते बनायेगा। इस तरह के रिकार्ड का रखरखाव अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक तरीके से करेगा। सी.पी.एफ.सी/आर.पी.एफ.सी के निर्देश अनुसार नियोक्ता समय समय पर सदस्यों के खातों का विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से संचारित करेगा।
14. न्यासी मंडल द्वारा हर कर्मचारी को उसके खाते का वार्षिक विवरण/पास बुक वित्तीय लेखा वर्ष के खत्म होने के छः महीने पहले एक बार के मामूली शुल्क में निशुल्क रूप से देगा। पास बुक के मामले में वह कर्मचारी के पास ही होगी और न्यासियों द्वारा समय समय पर, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत करने पर, उसे अद्यतन किया जायेगा।
15. नियोक्ता द्वारा उचित प्रावधानों के रूप में सदस्यों के लिये कंप्यूटर टर्मिनलों का इंतजाम करना होगा जिससे कि सदस्य जब चाहें अपने खाते में शेष राशि देख सकें।
16. न्यासी बोर्ड और नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मासिक/वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। ऐसा ना होने पर न्यासी मंडल तथा नियोक्ता संयुक्त रूप से अथवा अलग से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दंडात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा।
17. न्यासी मंडल द्वारा समय समय पर सरकार के निर्देशों के अनुरूप भविष्य निधि की राशि का निवेश करेगा। राशि का निवेश यदि सरकारी निर्देशों के अनुसार नहीं होता तो न्यासी मंडल पर संयुक्त रूप से अथवा अलग से कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिभार लगाया जा सकता है।
18. प्रतिभूतियों को ट्रस्ट के नाम पर प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त प्रतिभूतियों का डीमैट होना चाहिये और क्षेत्र में कथित सुविधा की उपलब्धता नहीं होने के कारण न्यासी मंडल इस की जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को देगा। न्यासी मंडल द्वारा एक रजिस्टर रखा जायेगा और सुनिश्चित करेगा कि ब्याज की वसूली समय पर की जाती रहे।

डीमैट खाता भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त किये गये डिपाजिट्री प्रतिभागियों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी नीतियों के अनुसार खोला जाये।

डीमैट खाता बनाये रखने की लागत को न्यासी द्वारा आकस्मिक लागत के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिये।

19. ऐसे सभी निवेश, प्रतिभूतियों और बॉण्ड की खरीद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त किये गये डिपाजिट्री प्रतिभागियों की सुरक्षित निगरानी में रखनी चाहिये जो उसके संरक्षक भी होंगे। प्रतिष्ठान के बंद होने पर अथवा परिसमापन पर अथवा ईपीएफ स्कीम, 1952 द्वारा छूट रद्द होन पर इस तरह के संरक्षक को सभी तरह के निवेश जो कि मंडल के नाम पर लिये गये हैं आरपीएफसी के अनुरोध पर स्थानांतरण करने होंगे।
20. छूट प्राप्त स्थापना आरपीएफसी को उन डिपाजिट्री प्रतिभागियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त के बारे में सूचित करेगी जिनके संरक्षण में निवेश ट्रस्ट के नाम किये गये थे जैसे निवेश प्रतिभूतियों और बॉण्ड के रूप में किये गये। हालांकि न्यासी मंडल इस तरह की राशि बैठकों के लिये अनिवार्य खर्च के रूप में जैसे दावों का निपटान, नियम के अनुसार भविष्य निधि सदस्य की राशि का स्थानांतरण नियोक्ता की सेवा छोड़ने के समय और प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा किसी अन्य तरह की प्राप्ति अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अनुमति पर फंड के नाम पर कोई अन्य निवेश।
21. किसी भी तरह का आयोग, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक प्रतिफल किसी भी वित्तीय अथवा अन्य संस्थान द्वारा दिया जाता है तो वह ट्रस्ट के खाते में जमा होगा।
22. नियोक्ता तथा न्यासी मंडल के सदस्यों को छूट के समय आर.पी.एफ.सी के समक्ष लिखित उपक्रम प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी यह सहमति होगी कि वह सभी शर्तों व नियमों का सदा पालन करेगा और यह कानूनी तौर पर नियोक्ता और न्यासी मंडल उनके उत्तराधिकारियों पर, संपत्ति भागी पर बाध्यकारी होगा।
23. नियोक्ता तथा न्यासी बोर्ड को छूट रद्द ना होने की स्थिति में संबंधित आरपीएफसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत हस्तांतरण करने के लिये एक उपक्रम देना होगा। यह कानूनी तौर पर उन पर बाध्यकारी होगा और उन्हें धन के हस्तांतरण में कोई देरी की स्थिति में अभियोजन पक्ष के लिये उत्तरदायी बनना होगा।
24. न्यासी मंडल द्वारा बनाये गयी भविष्य निधि के खाते को वार्षिक तौर पर एक योग्य स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन किया जायेगा। जहाँ आवश्यक माना जायेगा सी.पी.एफ.सी. अथवा क्षेत्र के आर.पी.एफ.सी प्रभारी द्वारा खातों की लेखा परीक्षा किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक द्वारा कराया जा सकता है जिसका खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।  
ऑडिटिड बैलेंस शीट तथा प्रलेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, की एक प्रति, नये वित्तीय वर्ष के 6 महीने खत्म होने के भीतर आर.पी.एफ.सी. को प्रस्तुत की जायेगी। बैलेंस शीट तथा अन्य जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित और एक हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में आर.पी.एफ.सी. कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।  
एक ही लेखा परीक्षकों को लगातार दो साल के लिये नियुक्त नहीं किया सकता और छः साल में दो बार से ज्यादा नहीं नियुक्त किया सकता।
25. स्थापना द्वारा लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक पूंजी के आधार पर अपने को घाटे में दिखाने पर दी गयी छूट को अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने के पहले दिन वापस ले लिया जायेगा।
26. छूट दी गयी संस्थापना के निरीक्षण के लिये केन्द्र सरकार को समय समय पर धारा 17 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (ए) अनुसार सुविधा हर महीने के खत्म होने के 15 दिन पहले प्रदान करनी होगी जिसके शुल्क का भुगतान नियोक्ता को भुगतान करना होगा।
27. छूट के अनुदान के लिये शर्तों के, नियोक्ता तथा न्यासी मंडल द्वारा, किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर दी गयी छूट कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरांत रद्द कर दी जायेगी।
28. किसी भी नुकसान, गबन, धोखाधड़ी गलत निवेश के निर्णय आदि पर नियोक्ता ही जिम्मेवार होगा और उसका भुगतान करेगा।
29. संस्थापना, जिसे छूट दी गयी है, की कानूनी स्थिति के किसी भी परिवर्तन, विलय, विघटन, अतिग्रहण, बिक्री एकीकरण, एक सहायक के गठन, चाहे पूर्ण स्वामित्व या नहीं, उसकी छूट रद्द की जायेगी और संस्थापना को पुनः ताजा छूट के अनुदान के लिये आर.पी.एफ.सी को रिपोर्ट करना होगा।
30. यदि छूट पायी हुई ट्रस्ट में एक से अधिक यूनिट/संस्थापना भाग ले रही है तो सभी न्यासी मंडल तथा नियोक्ता संयुक्त रूप से अथवा अलग से किसी भी यूनिट/स्थापना के किसी भी न्यासी द्वारा कोई भी चूक होती है तो आर.पी.एफ.सी सभी न्यासियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करेगा।
31. केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापना को मिलने वाली छूट को जारी रखने के लिये किसी भी प्रकार का नियम निर्धारित कर सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, सचिव (श्रम)

**LABOUR DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 17th January, 2017

**No.: F/29/17/EPF(Exemp.-4686)/Lab/16/4110.**—Whereas, M/s RHC Holding Pvt. Ltd. New Delhi (DL/4686), (herein after referred to as the said establishment) applied for exemption under sub-section (1) of section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Sub-Committee of Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund in its meeting dated 07.08.2014 has recommended that exemption under section (17)(1) of the said Act (19 of 1952) may be given to the said establishment with effect from 15.09.2009;

And whereas, in the opinion of the Lt. Governor, Delhi the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in the enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Fund Scheme, 1952 (herein after referred to as the said scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the said Act read with notification no. PF-II.11(40)/59 dated 22.04.1960 of Government of India, Ministry of Labour, subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Lt. Governor, Delhi hereby exempts the said establishment from the operation of the provisions of the Employees Provident Fund Scheme retrospectively with effect from 15.09.2009.

**SCHEDULE**

1. The employer shall establish a Board of Trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund in accordance to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time. The Provident Fund shall vest in the Board of Trustee who shall be responsible for and accountable to the employees' Provident fund organization, inter alia, for proper accounts of the receipt into and payment from the Provident Fund and the balance in the custody. For the purpose, the "employer" shall mean-the person who, or the authority, that has the ultimate control over the affairs of the establishments.
2. The Board of Trustee shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner (CPFC) or an officer authorized by him.
3. All employers, as defined in section 2(f) of the Act, who have been eligible to become members of the Provident Fund, had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.
4. Where an employee, who is already a member of Employees' Provident Fund or a member of provident fund of any other exempted establishment, is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund. The employer should also arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credits into his account.
5. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contribution payable to the provident fund by himself and by the employees at the rate prescribed under the Act from time to time by the 15<sup>th</sup> of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay

simple interest in terms of the provisions of section 7Q of the Act for any delay in payment of any dues towards the Board of Trustees.

6. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund and also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

7. Any deficiency in the interest declared by the Board of Trustees is to be made good by the employer to bring it up to the statutory limit.

8. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the funds as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto along with a translation in the language of the majority of the employees.

9. The rate of contribution payable, the conditions and quantum of advances and other matters laid down under the provident fund rules of the establishment and the interest credited to the account of each member, calculated on the monthly running balance of the member and declared by the Board of Trustees shall not be lower than those declared by the Central Government under the various provisions prescribed in the Act and the Scheme framed there under.

10. Any amendment to the Scheme, which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically pending formal amendment of the Rules of the trust.

11. No amendment in the rules shall be made by the employer without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner (referred to as RPFC hereinafter). The RPFC shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

12. All claims for withdrawals, advance and transfer should be settled expeditiously, within the time frame prescribed by the Employees Provident Fund Organization.

13. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contribution credited withdrawal and interest in respect of each employee. The maintenance of such records should preferably be done electronically. The establishments should periodically transmit the details of member's accounts electronically as and when direct by the CPFC/RPFC.

14. The Board of Trustees shall issue an annual statement of accounts or pass books to every employee within six months of the close of financial/accounting year free of cost once in the nominal charges. In case of passbook, the same shall remain in custody of employee to be updated periodically by the trustees when presented to them.

15. The employer shall make necessary provisions to enable all the members to be able to see their account balance from the computers terminals as and when required by them.

16. The Board of Trustees and the employer shall file such returns month/annually as may be prescribed by the Employees' Provident Fund Organization within the specified time-limit, failing which it will be deemed as a default and the Board of Trustees and employer will jointly and separately be liable for suitable penal action by the Employees' Provident Fund Organization.

17. The Board of Trustees shall invest the money of the provident fund as per the directions of the government from time to time. Failure to make investments as per directions of the Government shall made the Board of Trustees separately and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

18. (a) The securities shall be obtained in the name of Trust. The securities so obtained should be in dematerialized (DEMAT) form and in case the required facility is not available in the area where the trust operates, the Board of Trustees shall inform the Regional Provident Fund Commissioner concerned about the same.

(b) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest.

(c) The DEMAT Account should be opened through depository participants approved by Reserve Bank of India and Central Government in accordance with the instruction issued by the Central Government in this regard.

(d) The cost of maintaining DEMAT account should be treated as incidental cost of investment by the Trust. Also all types of Cost of investment by the Trust.

19. All such investments made, like purchase of securities and bonds, should be lodged in safe custody of depository participants, approved by Reserve Bank of India and Central Government, who shall be the custodian of the same. On closure of establishment or liquidation or cancellation of exemption from EPF Scheme, 1952, such custodian shall transfer the investment obtained in the name of the Trust and standing in its credit to the RPFC concerned directly on receipt of request from the RPFC concerned to that effect.

20. The exempted establishment shall intimate to the RPFC concerned the details of depository participants (approved by the Reserve Bank of India and Central Government), with whom and in whose safe custody, the investments made in the name of trust, viz., Investments made in securities, bonds, etc. have been lodged. However, the Board of Trustees may raise such sum or sums of money as may be required for meeting obligatory expenses such as settlement of claims, grant of advances as per rules and transfer of member's P.F. accumulations in the events of his/her leaving service of the employer and any other receipts by sale of the securities or other investments standing in the name of the Fund subject to the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner.

21. Any commission, incentive, bonus, or other pecuniary rewards given by any financial or other institutions for the investments made by the Trust should be credited to its account.

22. The employer and the members of the Board of Trustees, at the time of grant of exemption, shall furnish a written undertaking to the RPFC in such format as may be prescribed from time to time, inter alia, agreeing to abide by the conditions which are specified and this shall be legally binding on the employer and Board of Trustees, including their successors and assignees, or such conditions as may be specified latter for continuation of exemption.

23. The employer and the Board of Trustees shall also give an undertaking to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of exemption. This shall be legally binding on them and will make them liable for prosecution in the event of any delay in the transfer of funds.

24. (a) The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent chartered accountant annually. Where considered necessary, the CPFC or the RPFC in-charge of the Region shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

(b) A copy of the Auditor's report along with the audited balance sheet should be submitted to the RPFC concerned by the Auditors directly within six months after the closing of the financial year from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March. The format of the balance sheet and the information to be furnished in the report shall

be as prescribed by the Employees' Provident Fund Organization and made available with the RPFC Office in electronic format as well as a signed hard copy.

(c) The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than two years in a block of six years.

25. A company reporting loss for three consecutive financial years or erosion in their capital base shall have their exemption withdrawn from the first day of the next/succeeding financial year.

26. The employer in relation to the exempted establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of subsection (3) of section 17 of the Act within 15 days from the close of every month.

27. In the event of any violation of the conditions for grant of exemption, by the employer or the Board of Trustees, the exemption granted may be cancelled after issuing a show cause notice in this regard to the concerned persons.

28. In the event of any loss to the trust as a result of any fraud, defalcation, wrong investment decisions etc. the employer shall be liable to make good the loss.

29. In case of any change of legal status of the establishment, which has been granted exemption, as a result of merger, demerger, acquisition, sale amalgamation, formation of a subsidiary, whether wholly owned or not, etc., the exemption granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter to the RPFC concerned for grant of fresh exemption.

30. In case, there are more than one unit/establishment participating in the common Provident Fund Trust which has been granted exemption, all the trustees shall be jointly and separately liable/responsible for any default committed by any of the trustees/employer of any of the participating units and the RPFC shall take suitable legal action against all the trustees of the common Provident Fund Trust.

31. The Central Government may lay down any further condition for continuation of exemption of the establishments.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,  
A. K. SINGH, Secy. (Labour)